

कोरोना वायरस के प्रकोप की भारत सहित विश्व में फ़िर से आहट-विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों में ऐतिहासिक समझौता

(लेखक - एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी)

वैश्विक स्तरपर दुनियाँ का हर देश अभी तक कोरोना यारस (कोविड-19) की महामारी को भूल नहीं पाए है। यूं कहें कि संभल नहीं पाए हैं, इस बीच कोरोना महामारी के अनेक वैरिएट आ चुके हैं, लेकिन अभी मई में जो फिर से कोरोना यारस की आहट हुई है यह कोविड-19 तुल्य है, ऐसी जानकारी मीडिया में आ रही हालांकि इसका अधिक प्रकोप अभी खासकर हांगकांग औंगापुर थाईलैंड में स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। योकि संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। भारत भी 19 मई 2025 तक 257 केस आ चुके हैं, जिससे प्रासन प्रशासन स्वास्थ्य विभाग पूरी तरहसे अलर्ट मोड आ गए हैं, हालांकि सरकार और स्वास्थ्य एजेंसियां कोरोना की इस आहट को हल्के में लेने के मूड में नहीं सोभवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक हाई-लेवल रियू मीटिंग की बैठक बुलायी है।

टिंग बुलाई जिसमें एनसीडीसी, आईसीएमआर, सास्टर मैनेजमेंट सेल और केंद्र सरकार के अस्पतालों विशेषज्ञों ने भाग लिया, मीटिंग के बाद अधिकारियों ने जाया कि देश में कोविड की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण है, भारत का इटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम और आईसीएमआर के नेतृत्व में चल रहे जीनोम सीझेंसिंग पर्यक्तम लगातार कोरोना और अन्य श्वसन संक्रमणों पर जर बनाए हुए हैं, मंत्रालय ने साफ किया है कि उल्लाल यह चिंता की बात नहीं है, लेकिन सतर्कता चुर्री है, देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाकिसी भी संभावित क्रमण की लहर से निपटने के लिए तैयार है, परंतु इस दिनांक 20-21 मई 2025 की मध्यरात्रि में जिनेवा चल रहे विश्व स्वास्थ्य संगठन के विश्व स्वास्थ्य सभा, से 27 मई 2025 के 78 वें सत्र में सभा के सभी दस्त्यों की आपसी 3 वर्षों की बातचीत के उपरांत विष्य की महामारी में मिलकर तैयारी करने का मङ्गीता हो गया है, जो रेखांकित करने वाली बात है

और केंद्र सरकार के अस्पतालों के विशेषज्ञ मौजूद थे आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बैठक में यह निष्कर्ष निकाला गया न कि भारत में कोविड-19 स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। सूत्र ने बताया, 19 मई 2025 तक भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 257 है। देश की बड़ी आबादी को देखते हुए बहुत आंकड़ा कम है। इनमें से लगभग सभी मामले ज्यादा गंभीर नहीं हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत भी नहीं है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि बढ़ते मामलों को देखते हुए व्यापक तैयारी की जाए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 12 मई से 3 ब तक 164 मामले सामने आए हैं। केरल में सबसे अधिक 69 मामले, तो वहीं महाराष्ट्र में 44 और तमिलनाडु में 34 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कर्नाटक में कोविड-19 के 8 नए मामले, गुजरात में 6 और दिल्ली में 3 मामले सामने आए हरियाणा, राजस्थान और सिक्किम में एक-एक नया मामला सामने आया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक है इन घटनाक्रमों के महेनजर, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, आपातकालीन चिकित्सा राहत प्रभाग, आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और केंद्र सरकार के अस्पतालों के विशेषज्ञों की समीक्षा बैठक बुलाई गई, बैठक में निष्कर्ष निकाला गया कि भारत में वर्तमान कोविड-19 स्थिति नियंत्रण में है। 19 मई, 2025 तक, भारत में सक्रिय कोविड-19 मामलों की संख्या 257 है। जो देश की बड़ी आबादी को देखते हुए बहुत कम आंकड़ा है, इनमें से लगभग सभी मामले हल्के हैं, जिनमें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि सरकार और स्वास्थ्य एजेंसियां कोरोना की इस आहट को हल्के में लेने के मुद्दे में नहीं हैं। मीटिंग के

बाद अधिकारियों ने बताया कि देश में कोविड की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। भारत का इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम और आईसीएम आर के नेतृत्व में चल रहे जीनोम सीक्रेंसिंग कार्यक्रम लगातार कारोना और अन्य श्वसन संक्रमणों पर नजर बनाए हुए हैं, मत्रालय ने साफ किया है कि फिलाहाल यह चिंता की बात नहीं है, लेकिन सतर्कता ज़रूरी है, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था किसी भी संभावित संक्रमण की लहर से निपटने के लिए तैयार है। अगर पलू जैसे लक्षण हों तो टेस्ट कराएं, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, मास्क और सीनिटाइजर की आदत फिर से डालें, खासकर भीड़भाड़ वाली जगहों पर, किसी भी अफवाह या डर का शिकार न बनें, लेकिन सतर्क जरूर रहें।

साथियों बात अगर हम सिंगापुर हांगकांग थाईलैंड में कोरोना वायरस (कोविड-19) के अति तीव्रता से संक्रमण की करें तो, कोरोना वायरस एक बार फिर डराने लगा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ समय की राहत के बाद वायरस फिर से पैर पसारने लगा है, एशिया के कई देशों में कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, खासकर हांगकांग, सिंगापुर और थाईलैंड में स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। इन देशों में संक्रमितों की संख्या में तेज इजाफा हुआ है और अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। भारत में भी नए मामलों को लेकर चिंता गहराने लगी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अभी से सतर्कता नहीं बरती गई, तो स्थिति और बिंगड़ सकती है सिंगापुर में कोविड-19 के मामलों 28 परसेंट की गुद्धी दर्ज की गई है, हालात इन्हें बिंगड़ चुके हैं कि सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है यहां कोविड - 19 के कुल अनुमानित केस 14,200 तक पहुंच गए हैं, इससे ज्यादा गंभीर बात यह है कि अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में भी लगभग

परसेंट का इजाफा हुआ 15 मई से 11 मई के बीच गोपालगढ़ापुर में 25,900 नए केस सामने आए, इसी अवधि अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की औसत दैनिक छाया 181 से बढ़कर 250 हो गई है। विशेषज्ञों का नुमान है कि अगले 2 से 4 हफ्तों में यह लहर अपने रम पर पहुंच सकती है। हांगकांग में कोविड-19 क्रमण की नई लहर शुरू हो चुकी है, यहां स्थिति आतार बिंगड़ीती जा रही है, स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, यह तक 81 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 30 गों की मौत हो चुकी।

साथियों बात अगर हम डल्लूएचओ के विश्व स्वास्थ्य भारत के 78 वें सत्र में समझौतों की कर्त्ता तो, विश्व स्वास्थ्य भारत ने भविष्य की महामारियों के लिए तैयार रहने के लिए ऐतिहासिक समझौता अपनाया, विश्व का पहला मार्गदर्शन में जिनेवा में चल रहा है, ठन की शीर्षी निर्णय लेने की संस्था 78 वें विश्व स्वास्थ्य संगठन का यह ऐतिहासिक निर्णय कोविड-19 महामारी के विनाशकारी जबाब के जवाब में सरकारों द्वारा तीन साल से अधिक समय तक की गई बातचीत के बाद आया है, और इसका अस्थ भविष्य की महामारियों से दुनिया को सुरक्षित बनाना और उनके जवाब में अधिक न्यायसंगत बनाना है, इस डल्लूएचओ ने कहा। यह महत्वपूर्ण समझौता ऐसे समय में हुआ है जब सिंगापुर और हांगकांग सहित अन्य देशों में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि की खबरें आ रही हैं। साथियों बात अगर हम माननीय भारतीय पीएम द्वारा 10 जून 2025 को इस 78 वें सत्र को संबोधन की करें, तो इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य के लिए एक विश्व के मुद्दे पर बात की। पीएम ने कहा कि स्वस्थ विश्व का भविष्य नियंत्रण विभागीयता, एकीकृत दृष्टिकोण और सहयोग पर निर्भर रहता है।

संपादकीय

कोरोना संग जीना

दुनिया मानकर चल रही थी कोरोना संक्रमण का काला दौर हमेशा-हमेशा के लिये चला गया है। पिछले कुछ वर्षों से जन-जीवन फिर पटरी पर लौट रहा था। विश्व के कुछ क्षेत्रों में जारी युद्ध और अन्य विषम परिस्थितियों के बीच जारी आंतरिक उथल-पुथल के बावजूद अर्थव्यवस्थाएँ कोरोना से पहली स्थिति में पहुंचने के लिये जद्दोजहद कर रही थी। लेकिन कोरोना की नई दस्तक ने चिंताएँ बढ़ा दी हैं। कोरोना संक्रमण की वापसी की आहट पहले हांगकांग व सिंगापुर में सुनाई दी। हांगकांग में कुछ ही मामलों में तीस लोगों के मरने की खबर है। वही सिंगापुर में एक मई तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 14 हजार से अधिक थी, जिसमें 19 मई तक तीन हजार नये संक्रमित जुड़ गए हैं। जिस चीन से कोरोना वायरस सारी दुनिया में फैला, वहां भी कोरोना के मामले तो बढ़े हैं लेकिन इसके संख्या को सार्वजनिक नहीं किया गया। वही चीन का स्वास्थ्य विभाग कोरोना के मामलों में तेजी आने की आशंका जता रहा है। चिंता इस बात की भी है कि भारत में केरल, महाराष्ट्र व तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए। बताया जा रहा है कि एक जनवरी से 19 मई तक देश में ढाई सौ से अधिक संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। मुंबई के अस्पताल में भर्ती दो मरीजों की संक्रमण से हुई मौत को लेकर भी चिंता जातायी जा रही है। हालांकि, अस्पताल का दावा है कि एक रोगी कैसर तो दूसरा किंडनी से जुड़ी गंभीर यामारी से पीड़ित था। बहरहाल, कोरोना के नये वायरस के संक्रमण को लेकर सरकार के स्तर पर गंभीर प्रयास करने तथा नागरिकों को सजग-सतर्क रहने की जरूरत है कोरोना संक्रमण की पिछली कई लहरों से सबक लेकर उपचारात्मक नीतियों के क्रियान्वयन व चिकित्सा सुविधाओं को विस्तार देने की जरूरत है। इससे पहले कि वायरस अनियन्त्रित हो, सरकार व स्वास्थ्य एजेंसियों वाचव के उपाय युद्ध स्तर पर करने चाहिए। हालांकि, विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार के संक्रमण के लिये ओमिक्रोन के नये वेरिएट जे.ए.1 तथा वेरिएट एल.एफ.7 और एन.बी.18 जिम्मेदार हैं। बताया जा रहा है कि जे.एन.1 वेरिएट बहुत तेजी से फैलता है। विश्व के स्वास्थ्य विशेषज्ञ बता रहे हैं कि नये वेरिएट से पीड़ित लोगों में गले में खुराश, नींद न आना, छोंके आना, खांसी, एंजाइटी, नाक बहना, खांसी, सिरदर्द, कमजोरी, थकान व मांसपेसियों में दर्द की शिकायत शामिल हो सकती है। हालांकि, इनमें से कुछ आम इंफ्लूएंजा के लक्षण भी हो सकते हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण का टेस्ट करवाना भी जरूरी हो जाता है। वैसा कहना मुश्किल है कि कोरोना का वायरस हमारे बीच से चला गया। वह कहीं गया नहीं बल्कि टीकाकरण से मिली हमारे शरीर की रोगप्रतिरोधक क्षमता ने उसे रोक दिया। लेकिन दिक्षित यह है कि मौसम परिवर्तन वक्र के बीच में मृटौशन से इसके नये वेरिएट समाने आते हैं जिनका मुकाबला करने व शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को इहें समझने में शोड़ा वक्त लगता है। निस्संदेह, यह एक चुनौती है, लेकिन इससे घबराने की नहीं, समझदारी और सतर्कता से निपटने की जरूरत है। पिछली कई बड़ी कोरोना संक्रमण की लहरों ने हमें इस संक्रमण से मुकाबले के सबक दिए हैं। एक समय था जब हमारा चिकित्सा ढांचा इसके मुकाबले के लिये तैयार न था। जीवनदायिनी ऑवसीजन की उत्पादन क्षमता और भंडारण में हम अब आत्मनिर्भर हैं। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन अभियान चलाकर हमने 140 करोड़ लोगों को सुरक्षा कवच प्रदान किया है। हमने अपने नागरिकों को ही सुरक्षा कवच नहीं दिया, बल्कि परी दुनिया के अनेक देशों को भारत की वैक्सीन व चिकित्सा

(लेखक - ललित गर्ग)

पाकिस्तान भारत के अनेक लालची, शानोशैकत के आकांक्षी, पश्चिमांशद्रोही एवं देश के दुश्मन लोगों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ प्रधार और जासूसी गतिविधियों के लिए कर रहा था। ऐसे ही कुछ देश विरोधी तत्वों का पर्दाफाश होना चौकाता थी है एवं चिन्ता में भी डालता है। ऐसे ही तत्वों में एक नाम है ज्योति मल्होत्रा, उस पर आरोप है कि वह न बल्कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की सकारात्मक छवि पेश कर रही थी, बल्कि उसने पाक खुफिया एजेंसी के एजेंटों से भारत से जुड़ी विवेदनशील जानकारियां भी साझा कर रही थीं, जिनमें ॲपरेशन सिदूर जै जुड़ी गोपनीय जानकारियां भी थीं। वह एक खुफिया एजेंट के रूप में भीमा पार से चलाए जा रहे नेटवर्क का हिस्सा थी। देश की सुरक्षा जैसियों ने एक बार फिर सावित कर दिया है कि भारत की मिट्टी पर

पता यह भी चला है कि पाक यात्रा के उच्चायोग के एक कर्मचारी दानिश से हु पहचान आइसआइ के एजेंटों से हुई क्लाटसएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट के जर्मने एक पाक खुफिया अधिकारी के साथ साथ बाली भी गयी थी। ज्योति एवं उसके अति-संवेदनशील एवं गोपनीय सूचनाओं देश को नुकसान पहुंचा रहे थे। ये सभी 3 जी रहे थे, लेकिन इनके इरादे राष्ट्रविरोधी राष्ट्र-मूल्यों एवं निषाओं को ताक पर रख मौज-मस्ती का लक्ष्य धिनाना एवं अक्षर विस्फोटक विसंगतियों से बचाना होगा।

दौरान उसकी मुलाकात पाक ई, जिसके माध्यम से उसकी ज्योति इन एजेंटों के साथ रखे संपर्क में थी। कहते हैं कि वह गहरे संबंध बनाये और उसके के सहयोगी वेखीफ भारत की को पाक से साझा करते हुए नागरिकों की तरह जिंदगी की थी। देश की कीमत पर सारे लोगों कर धनार्जन की लालसा और अपराध है। राष्ट्र को इन कर्मचारी के संपर्क में थी, जिसे हाल ही में भारत विरोधी गतिविधियों के लिये देश से निकाला गया। इस मामले में चल रही जांच से पता चला है कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले से पहले ज्योति कश्मीर गई और उससे पहले पाकिस्तान गई थी। एक से अधिक बार पाकिस्तान जाचुकी ज्योति पर खुफिया अधिकारियों की नजर तो थी ही, ज्योति के कई वीडियोज ने भी खुफिया एजेंसियों का ध्यान खींचा, वाह वह नवी दिल्ली स्थित पाक दूतावास में इफ्तार की दावत का वीडियो हो, पिछले साल हुए विश्व कप में भारत-पाक मैच में दर्शकों की प्रतिक्रिया लाला वीडियो हो या कश्मीर घूमने आये लोगों पर बनाये गये वीडियो हों। विडबना है कि पाकिस्तान भारत में अभिव्यक्ति ली खतरंत्रत का गलत फायदा उठा रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक, ज्योति को दुर्बई के एक कथित हैंडलर के माध्यम से भुगतान किया जाता था।

भारत विराधी शाक्तया के हाथ में खलवा का नाम भी नहीं पर यह कृत्य परेशन एवं विना में डालना जासूसी कांड में लिपि ये भारतीय बड़े आश्रित एजेंटों के जाल में फँसे हों। लेकिन बड़ा प्रश्न व शानेशीकत के लालच में देश की सुरक्षा पर लगा सकते हैं? देश के भीतर के ये दुष्प्राणी घातक एवं नुकसानदेय हैं। पाकिस्तानी जताओं द्वारा खेलने पर देश की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिये प्रतिबद्ध है। ये गिरफ्तारियाँ भारत के लिये अत्यधिक दृष्टिशोध से महत्वपूर्ण एवं यह भी पाक की एक करारी हार ही है।

पाक के लिए जासूसी करने के आरोप में हरियाणा के हिसार की पट्टूयूबूर और ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा समेत छह लोगों की खुफिया दर्तनियों ने गिरी जानकारी के अधिकार पर की परीक्षणात्मकी शराब की जारी रखती है।

कर दश का मुश्कल म डालने ने वाला है। बहुत संभव है कि उक प्रलोभनों के लालच में पाक इस्तर है कि कैसे कुछ लोग पैसे भा व लोगों का जीवन भी दब दुश्मन बाहरी दुश्मनों से ज्यादा तासूसी एजेंसी आईएसआई से ज़ंजाब य यूपी के इन लोगों की है ए हैं। लेकिन इनकी गहन जांच गवानाओं को नकारा नहीं जा री कानून प्रवर्तन एजेंसियों और वे गंभीरता से लेना होगा। इन इसका पर्दाफाश होना ज्यादा के साथ ही साप्रदायिक सम्भाव सकते हैं।

वी ज्योति कथित तौर पर हाल

(चिंतन-मनन)



संकल्प और साहस

खेल की कक्षा शुरू हुई तो एक दुबली-पतली अपंग लड़की किसी तरह अपनी जगह से उठी। वह खेलों के प्रति जिज्ञासा प्रकट करते हुए शिक्षक से ओलिपिक रेकॉर्ड्स के बारे में सवाल पूछने लगी। इस पर सभी छात्र हँस पड़े। शिक्षक ने भी व्यग्र किया - तुम खेलों के बारे में जानकर क्या करोगी। अपने ऊपर कभी नजर डाली है? तुम तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती, फिर औलिपिक से तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हें कौन सा खेलना है जो यह

रुआंसी लड़की कुछ कह न सकी। सारे उस पर हंसती रही। अगले दिन जब खेल में उसे बाकी बच्चों से अलग बिटाया गया कुछ सोचकर बैसाखियां संभाली और ढूढ़ फैसाथ बोली—सर याद रखिएगा। अगर लग हो और इरादे बुलंद हों तो सब कुछ संभव देखना एक दिन यही लड़की हवा से बात दिखाएगी। उसकी इस बात से भी ठहाका ग सबने इसे मजाक के रूप में लिया। लौ

अच्छी और पौष्टिक खुराक लेने लगी, फिर वह कुछ दिनों में दौड़ने भी लगी। कुछ दिनों के बाद उसने छोटी-मोटी दौड़ में भाग लेना भी शुरू कर दिया। उसे दौड़ते देख लोग दांतों तले उंगली दबा लेते थे। फिर कई लोग उसकी मदद को आगे आए। सबने उसका उत्साह बढ़ाया। उसके हौसले बुलंद होने लगे। फिर उसने 1960 के ओलिंपिक में हिस्सा लिया और तीन स्वर्ण पदक जीतकर सबको हत्प्रभ कर दिया। ओलिंपिक में इतिहास रचने वाली वह थी अर्मेनी एथलिटिक टीम की ओमेली।

केंद्र की फंडिंग रोकने पर तमिलनाडु सरकार सपीस कोर्ट पहुंची

(लेखक- सन्तु शैव)

तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा अडिंग रोकने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में नीती दी है। तमिलनाडु सरकार का सुप्रीम कोर्ट जाना, भारत के संघीय ढांचे के अस्तित्व पर एक अहम सवाल खड़ा करता है। यह विवाद केवल आर्थिक संसाधनों के वितरण का नहीं है। इससे कहीं अधिक संवैधानिक अधिकारों, राज्यों की स्वायत्ता और केंद्र-राज्य संबंधों को लेकर एक बड़ा विवाद है। तमिलनाडु सरकार का आरोप है, समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत तमिलनाडु को 291.30 लरोड़ की राशि मिलनी थी। जिसे केंद्र सरकार ने रोक लिया है। तमिलनाडु राज्य ने अष्टीय शिक्षा नीति (नेप-2020) और पीएम

सरकार राज्यों के साथ इस तरकार रही है। संविधान में स्पष्ट एवं राज्य सरकार की समर्वता दी है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों आहम हैं। यदि कोई राज्य विभाग असहमति रखता है। ऐसी निष्फटिंग से विचित करना संविधान द्वारा के खिलाफ है। सहयोगात्मक परिकल्पना केवल भाषणों तक ही नहीं चाहिए। उसे व्यवहार में भी एवं राज्य सरकार दोनों के लिए है। तमिलनाडु सरकार का सुर्प्रिज़ केवल एक राज्य के संघर्ष का नहीं उन सभी राज्यों के लिए एक अभी तक केंद्र सरकार द्वारा नहीं किए जाए विवरात्मक तरीका

हैं, उसके विरोध में न्याय कोर्ट नहीं पहुंचे थे। केंद्र सरकार एक चेतावनी है। केंद्र सरकार और प्राथमिकताओं के अनुशासन करना चाहती है। सैफ़ सलाके द्वारा एवं राज्य सरकार द्वारियां पैदा करने वाला होगा याचिका पर न्यायालय का फैसला संबंधों को पारदर्शी और संतुष्टि दिशा में एक बड़ा कदम भी अन्य नए विवाद भी खड़ा होतमिलनाडु सरकार की याचिका कोर्ट द्वारा राज्यपाल और राज्य सीमा निर्धारित करने के बाबत यह विवाद तूल पकड़ता जा रहा है।

बीच खड़े हो सकते हैं। भारतीय लोकतंत्र की ताकत संघीय शासन की विविधता और विकेंद्रीकरण में निहित है। आवश्यक है, केंद्र सरकार शक्ति के केंद्रीकरण की बजाय राज्यों को विश्वास में लेकर भागीदार बनाए। राज्य सरकारें केंद्र के अधीनस्थ नहीं हैं। केंद्र एवं राज्य दोनों ही निर्वाचित सरकारें हैं। तभी भारत एक मजबूत और न्यायसंगत राष्ट्र है। पिछले एक दशक में केंद्र एवं राज्यों के बीच जिस तरह के विवाद देखने को मिल रहे हैं, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपाल निर्वाचित राज्य सरकार के ऊपर जिस तरह का अंकुश लगा रहे हैं, उसे लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ चुके हैं। उनके पक्ष में फैसला आया था, जेंटलमैन्स विवाद विभिन्न राज्यों की तात्पुरता के द्वारा सुनाया गया था। उन्होंने इस विवाद को अनुसार अनुसार देखा और उन्होंने अपनी विवादों की विविधता को देखा।

रकार ने अध्यादेश जारी कर पाल के अधिकारों को ज्यादा प्रभावी ता था। लेकिन अब जिन राज्यों के बाद खुलकर सामने आ रहे हैं यह पूर्ण दर्जा प्राप्त किए हुए हैं।
गण में इन्हें विशेष अधिकार प्राप्त हैं।
रकार यदि इन्हें अपने अधीनस्थ व्यवहार करेगी तो ऐसी स्थिति में गो संघवाद जो राष्ट्रीय एकता और का प्रतीक बना हुआ है, इसे ज्यादा एकजुट नहीं रखा जा सकेगा। भारत देश है जहां कई धर्म, कई भाषाओं, खान-पान, विभिन्न संस्कृति के साथ होकर पिछले 75 वर्षों से सांविधान के काम करता रहा है। यह कोई छोटी नहीं है।

सिंदूर मिटाने वालों को मिट्टी में मिलाया

22 अप्रैल का बदला, 22 मिनट में ले लिया
बीकानेर।

पाकिस्तान के सबक सीखने वाले ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार किसी सावर्जनिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम मोदी गुरुवार को बीकानेर पहुंचे। पीएम मोदी ने 26,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसके बाद जनसभा को संबोधित किया। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आतिकों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था। पहलानगम में चली गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों की छाती छलनी हो गई थी। सभी ने

एक जुट होकर संकल्प लिया कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देना है। और आज हम अपने प्रण में सफल हुए हैं। हमारी तीनों सेनाओं ने 22 मिनट में आतंकियों के 9 बड़े ठिकाने ध्वस्त कर दिए। पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। दुश्मन और दुनिया ने देखा कि सिंटूर जब बारूद बन जाता है तो क्या नतीजा होता है। उन्होंने कहा कि मैं देशवासियों से कहता हूं जो सिंटूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे-कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे कि भारत चुप रहगा। आज वो धरों में दुबके पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर धमंड करते हैं, आज वो मलबे के ढेर में ढबे हुए हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये शोध-प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर हैं। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है। ये समस्त भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था बार। अब सीधा सीने पर किया प्रह्लार है। आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही सीति है। यही भारत है, नया भारत है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंटूर, बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। मैं जब एयरस्ट्राइक के बाद आया था, तब मैंने कहा था कि सौंगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं छुकने दूंगा। आज मैं राजस्थान की धरती से देशवासियों से बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि देश के कोने-कोने में जो

तिरंगा यात्राओं का हुजूम चल रहा है। एटम बम की भभकियों से भारत डरने वाला नहीं पीएम मोदी ने कहा कि एटम बम की गोदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं है। हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग-अलग नहीं देखेंगे। उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। आपने देखा होगा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए हमारे देश के सात अलग-अलग प्रतिनिधिमंडल विश्वभर में पहुंच रहे हैं। इसमें देश के समस्त राजनीतिक दलों के लोग हैं। अब पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। पाकिस्तान भारत से कभी सीधी लड़ाई जीत भी नहीं सकता। जब भी सीधी लड़ाई होती है, तो बार-बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए पाकिस्तान ने आतंकवाद को भारत के खिलाफ लड़ाई का हथियार बनाया है। आजादी के बाद पिछले कई दशकों से यही चला आ रहा है। पाकिस्तान आतंक फैलाता था, निर्दोष लोगों की हत्या करता था।

भारत में डर का माहौल बनाता था लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया। अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तानकर खड़ा है।

मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है लेकिन लहू गर्म बहाता है। अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है। हार आतंकी हमले की चुकानी पड़ेगी भारी कीमत।

ਲਦਾਖ ਮੈਂ ਕਾਪਨੇ ਲਗੀ ਧਰਤੀ, ਲੋਗ ਘਰ ਦੇ
ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਰਾਤਮਾਰ ਮੂਕਾਪ ਲਕਨੇ ਕਾ
ਇੱਤਜਾਰ ਕਦਤੇ ਹੋ

लद्धाख

**बिहार में फिर वंदे भारत पर
बरसाए गए पत्थर, तोड़ डाले शीशे**



गया।

बिहार में बदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन एक बार फिर असामाजिक तत्वों के निशाने पर आ गई है। यथा जिले में कस्था रेलवे स्टेशन के पास बदे भारत एक्सप्रेस पर हुए हमले में ट्रेन के इंजन का एक शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना उस समय हुई जब ट्रेन बाराणसी से रांची की ओर जा रही थी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यह घटना बुधवार शाम को हुई, जब बदे भारत एक्सप्रेस कस्था रेलवे स्टेशन के पास से गुजर रही थी। अचानक कुछ असामाजिक तत्वों ने ट्रेन पर पत्थर फेंके, जिससे इंजन का एक शीशा टूट गया। इस घटना में सौभाग्य से कोई यात्री घायल नहीं हुआ। लेकिन, ट्रेन के क्षतिग्रस्त होने से रेलवे प्रशासन में हड्डकंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस (आरपीएफ) और स्थानीय पुलिस हरकत में आ गई। रेलवे पुलिस ने असामाजिक तत्वों की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी है। आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और सदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। रेलवे प्रशासन ने इस तरह की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। रेलवे पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसी गतिविधियों में शामिल न हों और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा में सहयोग करें। रेलवे प्रशासन ने यह भी कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे ट्रैक के आसपास निगरानी बढ़ावाइंद जाएगी और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। इस घटना ने एक बार फिर रेलवे संपत्ति की सुरक्षा और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जरूरत को उजागर किया है। रेलवे पुलिस ने जनता से अपील की है कि अगर उनके पास इस घटना से संबंधित कोई जानकारी है,

प्रधानमंत्री मोदी ने करणी माता मंदिर में की पूजा-अर्चना, देश को दी 26 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात

वीकानेर।



पुनर्विकसित देशनोक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने बीकानेर-मंबई एक्सप्रेस ट्रेन को ही डांड़ी

उनके द्वारा देश को दी जाने वाली सौमात्राओं के तौर पर ये परियोजनाएं न केवल यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाएंगी, बल्कि रेलवे चुनियादी ढांचे को आधुनिक और

भविष्य के लिए तैयार करने वाली साक्षित होंगी।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री का यह दौरा जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के ठीक एक महीने बाद हुआ है, जिससे इस यात्रा को और भी अधिक संवेदनशीलता और राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में देखा जा सकता है।

हमलों को विफल करने वाली कई एयर डिफेंस सिस्टम में से प्रत्येक

में 150-200 अग्निवीर थे। अग्निवीरों ने स्थानीय रूप से विकसित आकाशतीर वायु रक्षा नियंत्रण प्रणाली को संचालित करने में भी बड़ी भूमिका निभाई। यह प्रणाली दुश्मन के हमलों की त्वरित पहचान और जवाबी कार्रवाई में अहम सांबित हुई। आकाशतीर को पिछले वर्ष ही सेना में शामिल किया गया था और यह भारत की बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली का मुख्य हिस्सा बन गया है। पर्याप्तीमी मार्चें पर तैनात एडी यूनिट्स में अग्निवीरों को चार प्रमुख क्षेत्रों में विशेषज्ञता दी गई थी गनर्स, फायर कट्रोल ऑपरेटर्स, रेडियो ऑपरेटर्स और हैवी इयूटी क्वीकल ड्राइवर्स। उन्होंने एल-70, जे डियू-23-2-बी, ओसा-एके,

जानकारी दी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और पीओके स्थित नौ आतंकी चौकियों को तबाह किया थ। इसके बाल दोनों देशों के बीच काफी ज्यादा तनाव बढ़ गया।

बीएसएफ कमांडेंट ने कहा-
बीएसएफ ने उनकी गोलीबारी (पाकिस्तान द्वारा) का मुहोदा जवाब दिया। हमने उनको कहा-
संपत्तियों को नष्ट कर दिया।
मस्तपुर में उनका एक लॉन्च्यूड था, उस तबाह कर दिया गया है। हमारी कार्रवाई के कारण उनकी पांच चौकियां पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं।

जबलपुर। मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ने हिंदी भाषा में मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस निर्णय के अनुसार एमबीबीएस और डेंटल संकाय के जो छात्र-छात्रा हिंदी भाषा में परीक्षा देकर टॉप करेंगे। उन्हें मातृभाषा रत्न की उपाधि तथा नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। स्नातक पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा में टॉप करने वाले छात्र को 200000 रुपये की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। हर साल टॉप करने वाले विद्यार्थी को 100000 रुपये दिया जाएगा। यह योजना चिकित्सा शिक्षा में हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी की उच्च स्तरीय समिति की बैठक में

गीयों ने दिल्ली की आजीवनी वाक्ता

आरपाकस्तान का जवाब दगा।

यह निर्णय लिया गया है।

सार्वजनिक एवं निजी उपक्रम ट्रेनिंग पर किए खर्च को वसूल कर सकती हैं ट्रेनी से

ट्रेनिंग के बाद नौकरी छोड़ना नहीं होगा आसान

महत्वपूर्ण फैसला दिया हा। बिजया बैंक बनाम प्रशांत बी नरनाथरे प्रकरण में 14 मई को यह फैसला कोर्ट द्वारा सुनाया गया है। फैसले में कहा गया है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ और निजी क्षेत्र की कंपनियाँ अपने कर्मचारियों को ट्रेंड करती हैं। भरती करने में काफी पैसा खर्च करती हैं। उनसे सर्विस का बांड छापती है। उससे सर्विस उत्तम है। करने के लिए स्वतंत्र हा। बिजया बैंक का याचका क स्वीकार किया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र कंपनियों द्वारा जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए एक प्रक्रिया अपनाई। जिसमें भारी पैसा खर्च हुआ। उसके बाद ट्रेनिंग में पैसा खर्च किया। बीच मैं कोई अधिकारी या सर्विसी नौकरी छोड़ना आसान नहीं होगा। नौकरी छोड़ने पर उन नर्सर्स देते देते।

मराता हा उसका पालन करना कमचारा नाकरा छाड़कर जाता हा हजान दना होगा।

पांचारा, टुगुस्का जसा बूदूक और मिसाइल प्रणालियों को संभाला और अनेक राडार सिस्टम्स व संचार नेटवर्क का संचालन किया। मुश्किलों में काम आए अग्निवीर भारत-पाकिस्तान की इस लड़ाई ने अग्निपथ योजना की प्रासारिकता को एक बार फिर साबित किया। इस योजना को 2022 में लागू किया गया था। इसके तहत सैनिकों

महत्वपूर्ण फसलों दिया हा विजया बैंक बनाम प्रशांत बी नरनाथरे प्रकरण में 14 मई को यह फैसला कोर्ट द्वारा सुनाया गया है। फैसले में कहा गया है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां और निजी क्षेत्र की कंपनियां अपने कर्मचारियों को ट्रेंड करती हैं।

भरती करने में काफी पैसा खर्च करती हैं। उनसे सर्विस का बांड भराती है। उसका पालन करना करने के लिए स्वतंत्र हा।

सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए एक प्रक्रिया अपनाई।

जिसमें भारी पैसा खर्च हुआ। उसके बाद ट्रेनिंग में पैसा खर्च किया।

बीच मैं कोई अधिकारी या कर्मचारी नौकरी छोड़कर जाता है।

विजया बैंक का याचक का स्वीकार किया।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कंपनियों द्वारा जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति और ट्रेनिंग दी जाती है।

इस फैसले के बाद उनके लिए बीच मैं नौकरी छोड़ना आसान नहीं होगा। नौकरी छोड़ने पर उन्हें हजारा देना होगा।

